NYCS
RNI: DELBIL/2008/25219, ₹20

युवा सहकार

www.nycsindia.com
जुलाई 2025, नई दिल्ली

सहकारिता को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाने की तैयारी

सहकारी शिक्षा का नया युग शुरू 12

16 ऑटो उद्योग में कुशल कार्यबल और कौशल प्रशिक्षण की सख्त जरूरत

International Year of Cooperatives
2025
Cooperatives Build a Better World

KRIBHCO
Cooperative and beyond...

SERVING **FARMERS** **TO GROW** BOUNTIFUL

KRIBHCO world's premier fertilizer producing cooperative has been consistently making sustained efforts towards promoting modern agriculture and cooperatives in the country. It helps farmers maximize their returns through specialised agricultural inputs and other diversified businesses.

KRISHAK BHARATI COOPERATIVE LTD

Registered Office: A-60, Kailash Colony, New Delhi-110048 | **Phone: 011-29243412**
Corporate Office: KRIBCHO BHAWAN, A 8-10, Sector-1, Noida-201301, Distt: Gautam Budh Nagar (UP) | **Phones:** 0120-2534631/32/36
Website: www.kribhco.net | **KRIBCHO Kisan Helpline:** 0120-2535628 | **E-mail:** krishipramarsh@kribhco.net

OUR PRODUCTS

Neem Coated Urea | DAP | MOP | NPK | NPS | MAP | Liquid Bio Fertilizers | Certified Seeds | Hybrid Seeds
City Compost | Zinc Sulphate | Natural Potash | Sivarika | Rhizosuper

युवा सहकार

वर्ष : 02, अंक-01, जुलाई-2025

निदेशक मंडल
एनवाईसीएस

प्रकाश चंद्र साहू
मनीष कुमार
राजेश बाबूलाल पांडे
प्रकृति क्षितिज पंड्या
बालू गोपालकृष्णन
ज्योतिर्मय सिंह महतो
गौरव पांडेय
हिरेन मधुसूदन शाह
राघव गर्ग
आशुतोष सतीश गुप्ता

कार्यालय

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस)
209, द्वितीय तल, ए2बी, वर्द्धमान जनक मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058
मोबाइल नंबर : 9205595944
लैंडलाइन नंबर : 011-45096652/40153681
E-mail: nycs.ltd@gmail.com
Web: www.nycsindia.com

Registration No
DELBIL/2008/25219

संकल्पना, कंटेंट व डिजाइन : फार्च्यूना कम्यूनिकेशंस प्रा. लि., नई दिल्ली

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एवं जीएम ऑफसेट, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-92 द्वारा मुद्रित।

अभिषेक कुमार: पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के उत्तरदायी।

NYCSIndia

सहकारिता की दूसरी क्रांति 04

पहली बार भारतीय बना आईसीए यूथ कमेटी अध्यक्ष 05

06 सहकारिता को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाने की तैयारी

11 उभरती टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे पैक्स

दो वर्ष में 3.5 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य 18

अलग मंत्रालय से सहकारिता ने भरी नई उड़ान 20

सहकार टैक्सी: सहकारिता से बदलेगी परिवहन क्षेत्र की तस्वीर 24

इंश्योरेंस में भी कोऑपरेटिव, बनेगी नई कंपनी 26

बदलेगी खेलों की तकदीर व तस्वीर 28

एनवाईसीएस के कौशल विकास से मिली सफलता 30

सहकारिता की दूसरी क्रांति

सहकारिता को विस्तार देने के लिए कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की स्थापना बहुत बड़ी पहल है। इसके माध्यम से युवा अपने करियर के लिए नया विकल्प चुन सकेंगे। जब तक युवा इस क्षेत्र से नहीं जुड़ेंगे तब तक इसका विस्तार लक्ष्य के अनुसार नहीं हो सकेगा। युवा इस क्षेत्र से तभी जुड़ेंगे जब उन्हें इसमें अपना भविष्य और करियर नजर आएगा।

भारतीय सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने और 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने की जिस सोच के साथ केंद्रीय स्तर पर अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी, वह अब आकार लेने लगा है। अलग मंत्रालय की स्थापना को सहकारिता की दूसरी क्रांति की शुरूआत कहा जाए, तो अतिरेक नहीं होगा। मंत्रालय की स्थापना (6 जुलाई, 2021) को चार साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान मंत्रालय द्वारा सहकारी संस्थाओं की पुरानी कार्य प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और कारगर बनाने के लिए सहकारिता की निचली इकाई पैक्स से लेकर शीर्ष इकाई अपेक्स तक में व्यापक सुधार करने को लेकर 60 से अधिक पहल की गई है। इन चार वर्षों में उठाए गए कदमों और आगे उठाए जाने वाले कदमों को लेकर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 30 जून को नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ मंथन बैठक की।

सहकारी क्षेत्र की समीक्षा और भविष्य से जुड़ी नीतियों, नई पहलों एवं सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर दिन भर चली बैठक में गहन चर्चा हुई। इससे सहकारी विकास के लिए ठोस रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। इसी बैठक में केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने यह भी बताया कि नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति जल्द ही आने वाली है। यह नीति 2045 तक अमल में रहेगी। इसी के अनुसार हर राज्य अपनी-अपनी स्थिति के अनुरूप सहकारिता नीति बना सकेंगे और लक्ष्य निर्धारित कर सकेंगे। केंद्र सरकार आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक भारत को एक आदर्श कोऑपरेटिव देश बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए पूरे देश में सहकारिता के क्षेत्र में अनुशासन, नवाचार और पारदर्शिता लाने का काम किया जा रहा है जिसमें नई सहकारिता नीति काफी मददगार साबित होगी। उम्मीद है कि यह नीति अगले वर्ष जनवरी-फरवरी में घोषित हो जाएगी।

सहकारी आंदोलन को मजबूती देने के लिए सरकार देश की सभी सहकारी संस्थाओं को सशक्त बना रही है। इसमें वर्ष 2025 का महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि यह वर्ष अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान सहकारिता से देश की ज्यादातर आबादी, खासकर युवाओं को जोड़ने के लिए पहली बार कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। सहकारिता क्षेत्र को विस्तार देने के लिए यह बहुत बड़ी पहल है। इससे न सिर्फ सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इसके जरिये युवा अपने करियर के लिए नया विकल्प भी चुन सकेंगे। जब तक युवा इस क्षेत्र से नहीं जुड़ेंगे तब तक इसका विस्तार लक्ष्य के अनुसार नहीं हो सकेगा। युवा इस क्षेत्र से तभी जुड़ेंगे जब उन्हें इसमें अपना भविष्य और करियर नजर आएगा। इस यूनिवर्सिटी से युवा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कोर्स करने के साथ ही पीएचडी, रिसर्च आदि कर सकेंगे। स्कूली पाठ्यक्रम में भी सहकारिता को एक विषय के रूप में जोड़ने की पहल की जा रही है। आने वाले समय में सहकारी शिक्षा प्राप्त युवाओं को ही सहकारी संस्थाओं में नौकरी मिलेगी। इससे युवा इस क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे।

अभी सहकारी क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन की बहुत कमी है। अलग मंत्रालय बनने के बाद जिस तरह से देशभर में सहकारी क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है, उससे अगले पांच वर्ष में सहकारी क्षेत्र को 17 लाख कुशल पेशेवरों की जरूरत होगी। ऐसे में यह क्षेत्र युवाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहा है।■

प्रकाश चंद्र साहू
अध्यक्ष, नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

पहली बार भारतीय बना आईसीए यूथ कमेटी अध्यक्ष

युवा सहकार टीम

दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्था इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस (आईसीए) की यूथ कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में हर्ष संघाणी विजयी रहे हैं। आईसीए के 130 वर्ष के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी भारतीय को इस पद के लिए चुना गया है। ब्रिटेन के मैंचेस्टर में आईसीए की महासभा के दौरान आयोजित 'फेस्टिवल ऑफ कोऑपरेटिव्स' में हुए चुनाव में उन्हें विजय मिली। इससे पहले आईसीए-एशिया पेसिफिक के अध्यक्ष पद पर कोई भारतीय काबिज हुआ था। इस पद के लिए फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव कृभको के अध्यक्ष डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव चुने गए थे, जो अभी पद पर बने

हुए हैं। आईसीए दुनिया भर की कोऑपरेटिव सोसायटी का ग्लोबल ऑर्गनाइजेशन है।

आईसीए की यूथ कमेटी युवाओं का प्रतिनिधित्व करती है। युवाओं की आवाज को सहकारिता की नीतियों में शामिल करने, सहकारी उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और सहकारी संस्थाओं में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना इस कमेटी का मकसद है। हर्ष संघाणी का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दुनिया इस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मना रही है और भारत की इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी है। उनका चयन भारतीय युवाओं को सहकारिता के क्षेत्र में ग्लोबल स्तर पर सहयोग, नवाचार और नेतृत्व को बढ़ावा देने में मदद करेगा। उनके नेतृत्व में आईसीए की यूथ कमेटी कोऑपरेटिव नीतियों और अभ्यासों को नई पीढ़ी के लिए आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे यह संगठन न्याय, सशक्तीकरण और प्रतिस्थापन के मूल्यों को बढ़ावा देगा।■

विशाल सिंह बने बिस्कोमान अध्यक्ष

युवा सहकार टीम

सहकारी चुनाव प्राधिकरण (सीईए) ने बिहार कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन (बिस्कोमान) के ऑफिस बियरर्स के लिए 9 मई को हुए चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया है। एनसीसीएफ के अध्यक्ष विशाल सिंह बिस्कोमान के नए अध्यक्ष और महेश राय उपाध्यक्ष चुने गए हैं। बिस्कोमान का डायरेक्टर नामित करने को लेकर यह मामला झारखंड हाई कोर्ट में चला गया था जिसकी वजह से चुनाव परिणाम की घोषणा पर रोक लग गई थी। अब कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया है जिसके बाद नतीजे की घोषणा की गई है।

बिस्कोमान का चुनाव शुरू से ही विवादों में रहा है। दो दशक से ज्यादा समय तक इसके

अध्यक्ष रहे सुनील सिंह को पटखनी देने के लिए तमाम दांवपेंच चले गए। पहले तो उनका कार्यकाल खत्म होने पर पिछले साल उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और चुनाव कराने की घोषणा की गई। इस घोषणा के बावजूद विभिन्न वजहों से कई बार चुनाव को टाला गया। अंततः 24 जून, 2025 को बोर्ड के 17 सदस्यीय निदेशक मंडल के लिए चुनाव हुए। निदेशकों के चुनाव में सुनील सिंह पैनल के 12 सदस्य और विशाल सिंह पैनल के सिर्फ 5 सदस्य निदेशक चुने गए। इन्हीं निदेशकों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करना था। सुनील सिंह पैनल का पलड़ा भारी था लेकिन बिहार सरकार ने कानून का हवाला देते हुए बोर्ड में तीन निदेशक नामित कर दिए जिस पर आपत्ति जताते हुए झारखंड सरकार कोर्ट चली गई। इसी दौरान 9 मई को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया गया जिसमें नाटकीय तरीके से विशाल सिंह पैनल की जीत हो गई। चूंकि मामला कोर्ट में था इसलिए परिणाम घोषित नहीं किया गया। कोर्ट से मामला खारिज होते ही नतीजे घोषित कर दिए गए।■

सहकारिता को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाने की तैयारी

राष्ट्रीय सहकारिता नीति की जल्द होगी घोषणा, हर राज्य की नीति स्थानीय जरूरतों के अनुसार बनाने पर फोकस

युवा सहकार टीम

देश की अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र की संभावित भूमिका की अहमियत को देखते हुए सरकार इसके दायरे के विस्तार में जुट गई है। देश में युवा आबादी का बड़ा हिस्सा है और सरकार इनके लिए बड़े पैमाने पर अवसर उपलब्ध कराना चाहती है। केंद्र सरकार में सहकारिता क्षेत्र के लिए अलग मंत्रालय की स्थापना के चार वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 30 जून को सभी राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के साथ मंथन बैठक की। इस बैठक में भविष्य में सहकारिता

क्षेत्र में विस्तार के लिए क्षेत्रों व अवसरों की पहचान पर मंथन हुआ। इस दिशा में सरकार की पहली प्राथमिकता नई राष्ट्रीय सहकारी नीति लाना है। बैठक में केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार नई नीति लाने पर काम कर रही है। नई नीति अगले दो दशकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है।

इन चार वर्षों में सहकारिता क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए 60 से अधिक पहल की गई है। इनमें पैक्स का कंप्यूटरीकरण, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का निर्माण, पैक्स के लिए नए मॉडल बायलॉज को लागू करने, पैक्स का कारोबारी विस्तार, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना, डेयरी क्षेत्र में तीन नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाने, सहकार टैक्सी की शुरूआत करने और सहकारी क्षेत्र में पूर्ण स्वामित्व वाली बीमा कंपनी बनाने जैसे बड़े फैसले शामिल हैं। भारत के सहकारी क्षेत्र के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आयोजित 'मंथन' बैठक में सहकारी क्षेत्र से जुड़ी नीतियों, नई पहलों एवं सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर गहन चर्चा हुई। इससे सहकारी विकास के लिए ठोस रणनीति तैयार की जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और अमित शाह के दूरदर्शी मार्गदर्शन में केंद्र सरकार देशभर की सभी सहकारी संस्थाओं को सशक्त बना रही है, ताकि सहकारी आंदोलन को और मजबूत किया जा सके। यह मंथन बैठक इन्हीं प्रयासों का एक अभिन्न अंग थी।

मंथन बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना प्राचीन सहकारिता संस्कारों को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ नए परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर की है। देश में लगभग 60-70 करोड़ लोग ऐसे थे, जिनके पास जीवन जीने की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थीं। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने इन करोड़ों लोगों का जीवनस्वप्न पूरा कर दिया और इन्हें घर, शौचालय, पीने का पानी, अनाज, स्वास्थ्य, गैस सिलेंडर आदि सुविधाएं प्रदान कर दीं। ये करोड़ों लोग अब अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए उद्यम करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास पूंजी नहीं है। इन करोड़ों लोगों की छोटी-छोटी पूंजी से बड़ा काम करने का एकमात्र रास्ता सहकारिता है।' भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए दो चीजें बेहद जरूरी हैं, जीडीपी एवं जीएसडीपी का विकास और 140 करोड़ लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना।' उन्होंने कहा कि देश के हर व्यक्ति के लिए रोजगार के सृजन के लिए सहकारिता के सिवा कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसी दूरदर्शिता के साथ सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई।

केंद्र सरकार जल्द ही राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा करने वाली है। हर राज्य राष्ट्रीय नीति के तहत स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द सहकारिता नीति बनाए। साथ ही, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से जुड़कर सहकारी प्रशिक्षण को भी बढ़ावा दे।

अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में हुई यह बैठक सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम

अगले 5 वर्षों में हर गांव को कोऑपरेटिव से जोड़ना मोदी सरकार का लक्ष्य, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के उपयोग पर शाह ने दिया जोर

जल्द आएगी नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय नई राष्ट्रीय सहकारी नीति लाने पर काम कर रहा है। शाह ने बैठक में बताया कि जल्द ही राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा की जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल जनवरी में यह नीति घोषित हो जाएगी। यह नीति 2045 तक अमल में रहेगी। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति के तत्वाधान में ही हर राज्य की सहकारिता नीति वहां की सहकारिता की स्थिति के अनुरूप बनाई जाएगी और इसके लक्ष्य भी निर्धारित किए जाएंगे। पूरे देश में सहकारिता के क्षेत्र में अनुशासन, नवाचार और पारदर्शिता लाने का काम इस मॉडल एक्ट से होगा। केंद्र सरकार का प्रयास है कि आजादी के शताब्दी वर्ष 1947 तक भारत एक आदर्श कोऑपरेटिव देश बन जाए। शाह ने राज्यों के सहकारिता मंत्रियों से कहा कि 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स के निर्माण के निर्णय के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लक्ष्य को फरवरी महीने में ही हासिल कर लिया जाए, तभी हम 2 लाख पैक्स के लक्ष्य तक समय से पहुंच सकेंगे।

पांच वर्ष में हर गांव कोऑपरेटिव से जुड़ेगा

देश के करोड़ों छोटे किसानों और ग्रामीणों के कल्याण के लिए सहकारिता क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कानूनी, प्रशासनिक और वित्तीय सुधार किए गए हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री के अनुसार, इसके लिए सहकारिता मंत्रालय ने अब तक 60 से अधिक पहल की है। इन पहलों में से एक महत्वपूर्ण पहल

है राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का निर्माण, जिसकी मदद से सहकारिता क्षेत्र की कमियों को दुरुस्त किया जा रहा है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस इसीलिए बनाया गया है कि राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तहसील स्तर की सहकारी संस्थाएं मिलकर यह देख सकें कि किस राज्य के किस गांव में एक भी सहकारी संस्था नहीं है। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में देश में एक भी गांव ऐसा न रहे, जहां एक भी कोऑपरेटिव न हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का उपयोग करने पर शाह ने जोर दिया।

सरकार की पहलों का व्यापक मूल्यांकन

मंथन बैठक के दौरान सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों के व्यापक मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया गया, ताकि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं, नीति, सुझावों और कार्यान्वयन रणनीतियों के सार्थक आदान-प्रदान की सुविधा मिल सके। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ बैठक में किए गए विचार-विमर्श ने समावेशी विकास को प्राप्त करने में आपसी सहयोग और समन्वय के महत्व को रेखांकित किया। बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदुओं में देश भर में 2 लाख बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (एमपैक्स) की स्थापना की प्रगति और ग्रामीण सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को बढ़ावा देना शामिल था। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के कार्यान्वयन पर भी बैठक के दौरान विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में भाग ले रहे प्रतिनिधियों ने 'सहकारिता में सहकार' दृष्टिकोण के तहत अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में अपने योगदान को भी सामने रखा।

शिक्षण-प्रशिक्षण से बदलेगी सहकारिता की दिशा

देश में सहकारिता आंदोलन के पिछड़ जाने के पीछे तीन मुख्य कारण हैं। पहला, समय के साथ कानून नहीं बदले गए जिन्हें अब बदल दिया गया है। दूसरा, सहकारिता में अन्य गतिविधियों को नहीं जोड़ा गया या समय के साथ बदलाव नहीं किया गया। तीसरा, पहले सहकारिता क्षेत्र में सारी भर्तियां भाई-भतीजावाद से होती थीं। इसमें सुधार लाने के लिए ही त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। शाह ने राज्यों के सहकारिता मंत्रियों से आग्रह किया कि हर राज्य की कम से कम एक सहकारी प्रशिक्षण संस्था त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े, ताकि राज्य के कोऑपरेटिव सेक्टर की ट्रेनिंग की समग्र व्यवस्था इसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो। सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण से युक्त युवा जब सहकारी संस्थाओं से जुड़ेंगे तो इनका न केवल व्यापक विकास और विस्तार होगा, बल्कि इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होने से युवा इसमें अपना करियर भी बना सकेंगे।

सहकारिता में सहकार

सहकारिता क्षेत्र का विस्तार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने 'सहकारिता में सहकार' की परिकल्पना को सभी सहकारी संस्थाओं

कोऑपरेटिव बैंकों में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर

लंबे अरसे से कोऑपरेटिव बैंकों में दिक्कत बनी हुई थी। पारदर्शिता का अभाव भी इनके कामकाज में रहा है। अभी भी गाहे-बगाहे कोऑपरेटिव बैंकों में घोटाले के मामले आ रहे हैं। मंथन बैठक में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और क्रेडिट सोसायटी पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत महसूस की गई। अब कोऑपरेटिव बैंक को बैंकिंग एक्ट के तहत लाया जा चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी लचीलापन दिखाते हुए कोऑपरेटिव बैंकों की कई समस्याएं दूर की हैं। बाकी बची समस्याएं तभी दूर हो सकती हैं, जब पारदर्शिता के साथ बैंक का संचालन और कर्मचारियों की भर्ती होगी। बैठक में शाह ने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के संचालन में और अधिक पारदर्शिता लाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि सभी राज्यों के सहकारिता मंत्री अपने-अपने राज्यों में कृषि मंत्रियों के साथ समन्वय स्थापित कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें, ताकि आम लोगों के साथ-साथ जमीन का भी स्वास्थ्य सुधरे।

बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदुओं में देश भर में 2 लाख बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (एमपैक्स) की स्थापना की प्रगति और ग्रामीण सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को बढ़ावा देना शामिल था। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के कार्यान्वयन पर भी बैठक के दौरान विस्तृत चर्चा हुई।

इस उच्च स्तरीय मंथन बैठक में तीन नवगठित राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी समितियों- राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल), राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) के कामकाज का समर्थन करने में राज्यों की भूमिका की समीक्षा पर भी चर्चा की गई।

के लिए अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत सभी सहकारी संस्थाओं को अपना बैंक खाता कोऑपरेटिव बैंक में ही खोलने और उसी के माध्यम से लेनदेन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि वित्तीय लेनदेन के अलावा जितना संभव हो सके, अन्य लेनदेन भी सहकारी संस्थाएं एक दूसरे के माध्यम से ही करें। इससे सहकारी संस्थाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी। सहकारिता में सहकार का गुजरात में बहुत अच्छा और सफल प्रयोग हुआ है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि यह हमारी राष्ट्रीय क्षमता की वृद्धि और संवर्द्धन, राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता की ताकत बढ़ाने और कोऑपरेटिव की शक्ति का संवर्द्धन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहल है।

इस उच्च स्तरीय मंथन बैठक में तीन नवगठित राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी समितियों- राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल), राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) के कामकाज का समर्थन करने में राज्यों की भूमिका की समीक्षा पर भी चर्चा की गई। साथ ही एक सस्टेनेबल और सर्कुलर डेयरी अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य से श्वेत क्रांति 2.0 पहल पर विचार विमर्श किया गया। आत्मनिर्भर भारत के तहत दालों और मक्का के लिए समर्थन मूल्य पर खरीद से संबंधित नीतिगत मामलों पर भी प्रमुखता से चर्चा हुई।

मंथन बैठक में देश भर के सहकारिता मंत्रियों के अलावा राज्यों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और सहकारिता विभागों के सचिवों ने भाग लिया। इस दौरान केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों ने सहकारिता क्षेत्र में की जा रहीं प्रमुख डिजिटल परिवर्तन पहलों, जैसे पैक्स और राज्यों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) के कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण और राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की। बैठक के दौरान जिन अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई उनमें त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के माध्यम से क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण और सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए वित्तीय सुधार शामिल थे। इनमें राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए साझा सेवा इकाई का संचालन और शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन की स्थापना भी शामिल हैं। ■

उभरती टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे पैक्स

युवा सहकार टीम

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए इनका कंप्युटरीकरण किया जा रहा है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने अब 80,000 पैक्स का कंप्युटरीकरण करने का लक्ष्य रखा है। पैक्स के डिजिटलीकरण के बाद इन्हें समावेशी, जीवंत, निर्बाध और कुशलतापूर्वक कार्य करने लायक बनाया जाएगा। इसके लिए इन्हें उभरती टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा, ताकि किसानों और ग्रामीणों को इनके माध्यम से हर तरीके की सुविधाएं मिल सकें। केंद्रीय सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने 'पैक्स में उभरती प्रौद्योगिकियों' पर आयोजित एक कार्यशाला में यह जानकारी दी।

डॉ. भूटानी ने कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, 'हमारे किसानों और ग्रामीणों को मौसम संबंधी, आपदा संबंधी, वर्षा पूर्वानुमान, कीट हमले संबंधी सलाह की आवश्यकता है। आज ऐसी नई तकनीकें उपलब्ध हैं, जिन्हें हमारे ग्रामीण भारत को जागरूक और मजबूत बनाने के लिए सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। पैक्स कम्प्युटरीकरण योजना में अब तक लगभग 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब लक्ष्य 80,000 पैक्स का कम्प्युटरीकरण करना और भारत सरकार की सभी योजनाओं को पैक्स के साथ एकीकृत करके उन्हें जीवंत आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं में बदलना है।' पैक्स डिजिटलीकरण के लाभों की तुलना रेलवे के कम्प्युटरीकृत टिकट प्रणाली से करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण से पैक्स की कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता आएगी तथा यह अपने अस्तित्व के लिए व्यवहार्य और बड़े पैमाने पर समाज के लिए मूल्यवान बन जाएगा। पैक्स में भारत सरकार के लिए 'वन स्टॉप शॉप' बनने की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है। हमें बस यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि पैक्स अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए नवीनतम तकनीकों को अपनाएं।

पैक्स को समावेशी, जीवंत और निर्बाध, कुशलतापूर्वक और पारदर्शिता के साथ कार्य करने योग्य बनाने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा

डॉ. भूटानी ने कहा कि आज पैक्स की अल्पावधि ऋण सुविधाओं के माध्यम से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 42 प्रतिशत हो गई है। इससे पता चलता है कि पैक्स जैसी संस्थाएं ग्रामीण भारत के छोटे और सीमांत किसानों की सेवा करके स्पष्ट रूप से लाभकारी रही हैं। देश में करीब 2,000 बैंकिंग लाइसेंस में से 1,900 लाइसेंस सहकारी क्षेत्र में हैं और 100 लाइसेंस अन्य बैंकों के पास हैं। सबसे छोटी ऋण संरचनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ये नई तकनीक को अपनाने में अक्षम रही हैं, जिसके कारण सीमित बैंकिंग उत्पादों के साथ सहकारी बैंकों के कामकाज पर कुछ स्तर तक प्रतिबंध हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सहकारी क्षेत्र के बैंकिंग मुद्दों को आरबीआई, वित्त मंत्रालय और आयकर विभागों के साथ उठाया गया। अब समय आ गया है कि सहकारी बैंकिंग संरचना नई तकनीकों को अपनाए, अपने संचालन में पारदर्शिता लाए और अपने मानव संसाधन मुद्दों को हल करके खुद को प्रतिस्पर्धी बनाए।

सहकारिता सचिव ने कहा कि पहले पैक्स केवल ऋण या कृषि के लिए सामग्री प्रदान करने के लिए थे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मंत्रालय ने पैक्स को मजबूत करने और समाज के लिए उनकी भूमिका बढ़ाकर उन्हें व्यवहार्य बनाने का फैसला किया। पैक्स को सक्षम करने के लिए मॉडल बायलॉज बनाए गए, ताकि वे दो दर्जन से अधिक कारोबारी गतिविधियों में खुद को विविधता प्रदान करके आगे की आकांक्षा और आत्मनिर्भरता के साथ जीवित रह सकें।

इस कार्यशाला में डिजिटल इंडिया के युग में पैक्स, सटीक कृषि उपकरणों का लाभ उठाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और इंटरनेट टेक्नॉलाजी, कोऑपरेटिव फिनटेक और नीतिगत नवाचार तथा तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर और मिजोरम में सफलता की कहानियों पर भी चर्चा की गई।

सहकारी शिक्षा का नया युग शुरू

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 'त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी' का किया भूमि पूजन

सहकारिता आंदोलन में शिक्षण, प्रशिक्षण और नवाचार की कमी को पूरा करने का काम करेगी यह यूनिवर्सिटी, पूरे विश्व में सहकारिता का गढ़ बनेगा भारत

पारदर्शिता, जवाबदेही, अनुसंधान और सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ाने के लिए स्थापित हो रही त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी

युवा सहकार टीम

सहकारिता क्षेत्र में शिक्षण-प्रशिक्षण और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित की गई देश की पहली सहकारिता यूनिवर्सिटी के भवन निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन के साथ ही देश में सहकारी शिक्षा के क्षेत्र में नया अध्याय लिखने की शुरूआत हो चुकी है। इस यूनिवर्सिटी में युवाओं को तकनीकी विशेषज्ञता, अकाउंटेंसी, वैज्ञानिक सोच और मार्केटिंग के साथ-साथ सहकारिता के संस्कार सीखने को मिलेंगे। यहां से शिक्षित-प्रशिक्षित युवाओं को ही सहकारी संस्थाओं में नौकरी दी जाएगी। गुजरात के आणंद स्थित ग्रामीण प्रबंधन संस्थान (इरमा) के परिसर में 125 एकड़ में 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 'त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी' का भूमि पूजन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 जुलाई को किया। इसी के साथ यह तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। सहकारिता राज्य मंत्रियों कृष्णपाल गुर्जर एवं मुरलीधर मोहोल सहित देश के दर्जनों सहकारी दिग्गज इस ऐतिहासिक तारीख के गवाह बने।

इस यूनिवर्सिटी का नाम देश में सहकारिता आंदोलन के संस्थापकों में शामिल त्रिभुवन दास किशिभाई पटेल के नाम पर रखा गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 'आज का दिन सहकारिता क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने त्रिभुवन दास पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की नींव पारदर्शिता, जवाबदेही, अनुसंधान और सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ाने के लिए डाली गई है। इसके नाम के लिए त्रिभुवनदास पटेल से बेहतर व्यक्ति कोई नहीं हैं।' अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा, 'आणंद की धरती से ही श्रद्धेय त्रिभुवनदास पटेल जी ने सहकारिता के माध्यम से गरीबों, महिलाओं और किसानों के जीवन में परिवर्तन की अलख जगाई थी। उनके नाम से स्थापित होने जा रही यह यूनिवर्सिटी युवा शक्ति को सहकार शक्ति से जोड़ने का एक युगांतरकारी प्रयास

है। आने वाले समय में इस विश्वविद्यालय की शाखाएं देश भर में स्थापित की जाएंगी, जहां से प्रशिक्षित युवा सहकारिता को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक प्रबंधन के साथ आगे ले जाएंगे।'

सहकारी शिक्षण-प्रशिक्षण को बढ़ावा

वर्ष 2025 संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 'अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है। इसी वर्ष के दौरान त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए संसद में कानून बनाया जाना और इसके निर्माण की त्वरित प्रक्रिया का शुरू किया जाना यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के पीछे अमित शाह की ही सोच रही है। इस नाते उनके लिए भी यह चुनौती रही है कि जल्द से जल्द इस यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य पूरा किया जाए और यहां शिक्षण शुरू किया जाए।

देश के करोड़ों गरीबों और ग्रामीणों के जीवन में आशा का संचार करने और उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए चार साल पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की थी। अपनी स्थापना के बाद से पिछले 4 साल में सहकारिता मंत्रालय ने भारत में सहकारिता क्षेत्र के विकास, संवर्द्धन और समविकास के लिए 60 नई पहल की हैं। ये सभी पहल सहकारिता आंदोलन को चिरंजीव, पारदर्शी, लोकतांत्रिक बनाने, विकसित करने, सहकारिता के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने और सहकारिता आंदोलन में मातृशक्ति और युवाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए की गईं। इन्हीं पहल में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना भी शामिल है।

सहकारिता की कमियों को दूर करेगी यूनिवर्सिटी

अमित शाह ने यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने के दौरान कहा कि त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने में रह गई सभी कमियों को पूरा करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज देशभर में सहकारिता आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक युगांतकारी कदम है। आज देश भर में 40 लाख कर्मी सहकारिता आंदोलन के साथ जुड़े हैं। 80 लाख बोर्ड के सदस्य हैं और 30 करोड़ लोग, यानी देश का हर चौथा व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है। 30 करोड़ सदस्यों वाले सहकारी आंदोलन में शिक्षा, प्रशिक्षण और नवाचार की कमी को पूरा करने का काम यह सहकारी यूनिवर्सिटी करेगी। यह यूनिवर्सिटी नीतियों का निर्माण करेगी। नवाचार को बढ़ावा देगी। अनुसंधान की नींव डालेगी, प्रशिक्षण देगी और देश भर के सहकारी संस्थाओं के प्रशिक्षण का

स्कूलों के लिए सहकारी शिक्षा मॉड्यूल लॉन्च

भारत के सहकारी आंदोलन के बारे में स्कूली छात्रों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल करते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के सहयोग से सहकारिता पर एक विशेष द्विभाषी शैक्षिक मॉड्यूल पेश किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री शाह ने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के शिलान्यास समारोह के दौरान इस मॉड्यूल का औपचारिक अनावरण किया। हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किए गए इस मॉड्यूल को संवादात्मक, सुलभ और छात्र-अनुकूल बनाया गया है। यह स्कूली पाठ्यक्रम में सहकारी शिक्षा को शामिल करने और युवाओं को सहकारी मूल्यों से परिचित कराने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह मॉड्यूल छात्रों को प्राचीन भारत से सहकारी समितियों की अवधारणा, उनकी संवैधानिक स्थिति, सिद्धांतों और मूल्यों तथा स्वतंत्रता से पहले और बाद में उनकी भूमिका जैसे विषयों से परिचित कराता है। इसमें प्रमुख सहकारी नेताओं, सहकारी समितियों के विभिन्न रूपों और मंत्रालय की हालिया पहलों को भी शामिल किया गया है।

सहकारिता मंत्रालय ने कक्षा छह और उससे ऊपर के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में सहकारी विषय शामिल करने और कक्षा 11 और 12 के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में सहकारिता शुरू करने की योजना की भी घोषणा की। इससे छात्र त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों से और अधिक जुड़ सकेंगे। यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि 'सहकारिता एक विचार नहीं, एक आंदोलन है' का संदेश देश के हर युवा शिक्षार्थी तक पहुंचे।

पिछले 4 साल में सहकारिता मंत्रालय ने भारत में सहकारिता क्षेत्र के विकास, संवर्द्धन और समविकास के लिए 60 नई पहल की हैं। ये सभी पहल सहकारिता आंदोलन को चिरंजीव, पारदर्शी, लोकतांत्रिक बनाने, विकसित करने, सहकारिता के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने और सहकारिता आंदोलन में मातृशक्ति और युवाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए की गईं।

त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर यूनिवर्सिटी

इस यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन दास किशिभाई पटेल के नाम पर रखा गया है। त्रिभुवन दास पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के मार्गदर्शन में आणंद की भूमि पर ही एक नए विचार का बीज बोने का काम किया था। उन्होंने दूध इकट्ठा करने की एक छोटी सी मंडली बनाई और उसके माध्यम से किसानों को सशक्त करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। 1946 में खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ की स्थापना हुई और आज त्रिभुवन दास द्वारा बोया गया वह बीज 'अमूल' के रूप में एक विशाल वट वृक्ष बनकर खड़ा है। इससे 36 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। इसका कारोबार 80 हजार करोड़ रुपए का है। आज अमूल विश्व में खाने-पीने की चीजों का सबसे मूल्यवान ब्रांड बनकर उभरा है। त्रिभुवन दास पटेल के ही विजन के कारण दुनियाभर की निजी डेयरियों के सामने आज देश की कोऑपरेटिव डेयरी सीना तानकर खड़ी है। शाह के अनुसार, एक सहकारी नेता सहकारिता के हर सदस्य की भलाई के लिए जब काम करता है, तो राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र को समृद्ध बनाने की प्रक्रिया में कितना बड़ा योगदान दे सकता है, इसका आदर्श उदाहरण त्रिभुवन दास जी ने प्रस्तुत किया था।

एक समान कोर्स तैयार कर सहकारिता को एक साथ आगे बढ़ाने का काम करेगी। यह यूनिवर्सिटी प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म देने का काम करेगी और यहीं से सहकारिता की नीति बनेगी, जो सबका मार्गदर्शन करेगी।

कुशल मानव संसाधन की मांग होगी पूरी

केंद्रीय सहकारिता मंत्री के अनुसार, सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए सहकारिता के कर्मचारियों और सहकारी समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए पहले कोई सुचारू व्यवस्था नहीं थी। पहले कोऑपरेटिव में भर्ती के बाद कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी बनने के बाद जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, उसी को सहकारी क्षेत्र में नौकरी मिलेगी। इसके बनने से सहकारिता क्षेत्र में भाई-भतीजावाद खत्म हो जाएगा और पारदर्शिता आएगी। सहकारी यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षित युवा ही सहकारी संस्थाओं के लिए पात्र होंगे। भारतीय सहकारिता क्षेत्र के लिए कुशल मानव संसाधन की मांग पूरी करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस यूनिवर्सिटी में युवा तकनीकी विशेषज्ञता, अकाउंटेंसी, वैज्ञानिक अप्रोच और मार्केटिंग के सभी गुर तो सीखेंगे ही, साथ ही उन्हें सहकारिता के संस्कार भी सीखने को मिलेंगे। सहकारिता आंदोलन देश के दलित, महिलाओं और आदिवासियों के लिए है। सहकारी क्षेत्र की कई समस्याओं का समाधान इस सहकारी यूनिवर्सिटी से हो जाएगा।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में 2 लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) बनाने का निर्णय लिया है, जिनमें से 60 हजार नए पैक्स इस वर्ष के अंत तक बन जाएंगे। 2 लाख पैक्स में ही 17 लाख कर्मचारी होंगे। इसी प्रकार, कई जिला डेयरी बन रही हैं। इन सबके लिए कुशल मानव संसाधन की जरूरत होगी, जिसे त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी पूरा करेगी। यह यूनिवर्सिटी सहकारिता में नीति निर्माण, डेटा विश्लेषण और देश के कोऑपरेटिव के विकास की 5 साल, 10 साल और 25 साल की रणनीति बनाने का काम करेगी। अनुसंधान को भी इस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा गया है। यह

यूनिवर्सिटी सिर्फ सहकारी कर्मचारी तैयार नहीं करेगी, बल्कि यहां से त्रिभुवन दास पटेल जैसे समर्पित सहकारी नेता भी निकलेंगे, जो भविष्य में सहकारिता क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे। अमित शाह ने बताया कि 2 लाख नए और 85 हजार पुराने पैक्स के माध्यम से सभी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम भी यह विश्वविद्यालय करेगा। सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में सहकारिता विषय को जोड़ा है। गुजरात सरकार को भी अपने पाठ्यक्रम में सहकारिता विषय को जोड़ना चाहिए जिससे आम लोग सहकारिता के बारे में जान सकें।

यूनिवर्सिटी से जुड़ें सहकारी विशेषज्ञ

इस यूनिवर्सिटी के बन जाने से न सिर्फ देश का सहकारिता आंदोलन फलेगा, फूलेगा और आगे बढ़ेगा बल्कि पूरे विश्व में भारत सहकारिता का गढ़ बनेगा। त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई जाने वाली नीतियां और अभ्यासक्रम सहकारिता के आर्थिक मॉडल को एक जनआंदोलन में परिवर्तित करने का काम करेंगे। सभी बड़ी सहकारी संस्थाओं के लिए योग्य कर्मचारी प्रदान करने का काम यह यूनिवर्सिटी करेगी। शाह ने कहा कि हम कोऑपरेटिव टैक्सी लाना चाहते हैं, कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी भी बनाना चाहते हैं, तो हमें हर क्षेत्र के माहिर अधिकारी, कर्मचारी और सहकारी नेता भी चाहिए। पूरे देश के सहकारिता क्षेत्र का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि देशभर के सहकारिता प्रशिक्षण विशेषज्ञ इस यूनिवर्सिटी से जुड़ें और अपना योगदान दें।■

सभी सहकारी संस्थानों को जोड़ेगी यूनिवर्सिटी

त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी में डेयरी, मत्स्य, चीनी, बैंकिंग, ग्रामीण ऋण, सहकारी वित्त, सहकारी मार्केटिंग और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को पाठ्यक्रम में खासतौर पर प्रमुखता दी जाएगी। जिन राज्यों में सहकारी संस्थाओं की अधिकता है उनमें चार से पांच कॉलेजों को सहकारी विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाएगा और बाकी राज्यों में एक से दो सहकारी कॉलेज इससे संबद्ध किए जाएंगे। इसे वैश्विक स्तर के सहकारी विश्वविद्यालयों और सहकारी संस्थानों से भी संबद्ध किए जाने का प्रावधान किया गया है। यह सहकारी प्रबंधन संस्थानों को जोड़ने की एक कड़ी होगी। देश भर की स्कूली शिक्षा प्रणाली में इसे शामिल किया जाएगा। इसके पहले चरण में एनसीईआरटी की पुस्तकों के पाठ्यक्रमों में सहकारिता को शामिल किया जाएगा। सहकारी संस्थाओं के अलग-अलग प्रशिक्षण और प्रबंधन डिप्लोमा व डिग्री कार्यक्रमों का डिटेल तैयार कर लागू करेगा। इसमें पारंपरिक भारतीय आर्थिक दर्शन को समकालीन प्रबंधन तकनीकों के साथ एकीकृत किया जाएगा।

वैदिक परंपराओं से प्रेरित होकर छात्र इसमें स्थायी कृषि पद्धतियों, नैतिक व्यावसायिक आचरण और समुदाय-संचालित आर्थिक मॉडल के बारे में सीखेंगे। विश्वविद्यालय का एक अन्य उद्देश्य पूरे भारत में सहकारी शिक्षा को मानकीकृत करना है। सहकारी विश्वविद्यालय एक केंद्रीय संस्थान के रूप में भी कार्य करेगा जो आईसीएआर केंद्रों, कृषि विज्ञान केंद्रों, सीएसआईआर संस्थानों, स्वास्थ्य संबंधी संस्थानों और अन्य विश्वविद्यालयों से संसाधनों को जोड़ेगा। पैक्स सचिवों को भी यहां प्रशिक्षित किया जाएगा। पारंपरिक एमएसपी मॉडल से आगे बढ़ाते हुए यह विश्वविद्यालय सहकारी समितियों को बाजार-संचालित समाधान और आत्मनिर्भर व्यवसाय मॉडल अपनाने में मदद करेगा। इसके साथ ही यह विश्वविद्यालय ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए सहकारी मॉडल विकसित करने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगा, जिससे सस्ती चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित होंगी।

ऑटो उद्योग में कुशल कार्यबल और कौशल प्रशिक्षण की सख्त जरूरत

नीतेश के. चौरसिया
सहायक उपाध्यक्ष – उद्योग सहभागिता
ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल

भारत का ऑटोमोटिव उद्योग न केवल देश के आर्थिक विकास का एक अहम स्तंभ है, बल्कि यह सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं में से एक है। यह क्षेत्र निर्माण, बिक्री, सेवा और अनुसंधान जैसे अनेक उपक्षेत्रों में युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। आज जब यह उद्योग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन और ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तो इसके साथ-साथ एक नए प्रकार के कुशल कार्यबल की आवश्यकता भी उत्पन्न हो रही है।

भारत 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में तकनीकी बदलाव इस उद्योग की कार्यप्रणाली को तेजी से बदल रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का उदय, हाइब्रिड और हाइड्रोजन फ्यूल तकनीक का विकास, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का उत्पादन प्रक्रियाओं में उपयोग, कनेक्टेड कार्स और आईओटी आधारित समाधान, एआई और डेटा एनालिटिक्स की सेवा क्षेत्र में बढ़ती भूमिका जैसे बदलावों के बीच एक बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हमारा कार्यबल इन बदलावों के लिए तैयार है?

कुशल कार्यबल की कमी गंभीर चुनौती

विभिन्न रिपोर्ट्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अध्ययन बताते हैं कि परिपक्व होने के बावजूद भारतीय ऑटो उद्योग आज भी उपयुक्त और प्रशिक्षित कार्यबल की भारी कमी का सामना कर रहा है। विशेष रूप से, ईवी टेक्नोलॉजी, ड्यूल-स्किल्ड मेंटेनेंस स्टाफ, बैटरी टेक्निशियन, अडास (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे क्षेत्रों में कुशल श्रमबल की मांग तेजी से बढ़ रही है। बड़े पैमाने पर नए कॉलेज ग्रेजुएट्स तकनीकी रूप से मजबूत नहीं होते, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम और प्रयोगात्मक प्रशिक्षण उद्योग की बदलती मांगों से मेल नहीं खाते।

ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल (एएसडीसी) ऑटो उद्योग में उपयुक्त और प्रशिक्षित कार्यबल की कमी को दूर करने

के लिए लगातार प्रयासरत है। एएसडीसी सरकार, उद्योग और युवाओं के बीच सेतु के रूप में तीन स्तरीय भागीदारी मॉडल पर कार्य करता है। पहले स्तर पर यह सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (नएपीएस), नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) आदि और युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों को आपस में जोड़ता है। दूसरे स्तर पर यह उद्योग की स्किलिंग जरूरतों को समझकर उपयुक्त जॉब रोल्स और ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करता है। तीसरे और अंतिम स्तर पर अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार, अप्रेंटिसशिप और स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाता है।

प्रशिक्षण में नवाचार की आवश्यकता

आज कौशल विकास को केवल क्लासरूम ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। इसके लिए छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही इंडस्ट्री का अनुभव देना, खासकर ईवी और ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी में, जरूरी है। ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में पहुंच बढ़ाने के लिए ऑनलाइन और हाइब्रिड कोर्स उपलब्ध कराना, अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी काम करते हुए सीखते हैं, की अनिवार्यता और शिक्षकों को भी समय-समय पर उद्योग के अनुरूप प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। भारत सरकार के विभिन्न मिशन जैसे पीएमकेवीवाई, एनएपीएस, समर्थ उद्योग, ऑटो और ईवी के लिए पीएलआई स्कीम आदि स्किलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। मगर इन प्रयासों को तभी बल मिलेगा जब निजी उद्योग, सरकारी तंत्र और स्किल डेवलपमेंट संस्थान एक मंच पर आकर सहयोग करें। कंपनियों को चाहिए कि वे सीएसआर फंड का उपयोग स्किलिंग के लिए करें। इंडस्ट्री को इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप स्लॉट्स बड़ी संख्या में देने होंगे। साथ ही, सरकार को स्किलिंग को शिक्षा के साथ एकीकृत करना होगा, न कि एक वैकल्पिक रास्ता मानना चाहिए।

जैसे-जैसे ऑटोमोटिव उद्योग का विस्तार होता जाएगा, कुशल कार्यबल की आवश्यकता कई गुना बढ़ने की संभावना है। इनमें सॉफ्ट स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन माइंडसेट और डिजिटल लिटरेसी भी शामिल होगी। हमें ऐसे युवाओं को तैयार करना होगा जो सिर्फ तकनीकी रूप से ही नहीं, बल्कि भावनात्मक और संचार कौशल में भी दक्ष हों। ऑटोमोटिव उद्योग की गति को बनाए रखने के लिए कुशल कार्यबल सबसे बड़ा इंजन साबित होगा। हमें कौशल विकास को केवल एक कार्यक्रम या योजना न मानकर, राष्ट्र निर्माण का माध्यम समझना होगा। यदि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभानी है, तो हर युवा को उद्योगों की जरूरतों के अनुसार तैयार करना ही एकमात्र रास्ता है।

एएसडीसी के तहत सीएसआर गतिविधियां

एएसडीसी उद्योगों के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) उद्देश्यों को पूरा करने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। कई ऑटोमोटिव कंपनियां अपने सीएसआर फंड के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में निवेश कर रही हैं, जिनमें एएसडीसी एक विश्वसनीय ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करता है। इन सीएसआर गतिविधियों में वंचित वर्गों के युवाओं को निःशुल्क या रियायती स्किल ट्रेनिंग प्रदान करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अडास, आईओटी और ग्रीन मोबिलिटी जैसे आधुनिक विषयों पर प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना एवं संचालन, महिला सशक्तीकरण के लिए विशेष स्किलिंग प्रोग्राम्स, स्कूल और कॉलेज स्तर पर कौशल जागरूकता अभियान का संचालन और स्थानीय उद्योगों के साथ अप्रेंटिसशिप व रोजगार मेलों का आयोजन शामिल हैं। इनके माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि जरूरत के मुताबिक श्रमबल तैयार किया जा सके।■

जैसे-जैसे ऑटोमोटिव उद्योग का विस्तार होता जाएगा, कुशल कार्यबल की आवश्यकता कई गुना बढ़ने की संभावना है। इनमें सॉफ्ट स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन माइंडसेट और डिजिटल लिटरेसी भी शामिल होगी। हमें ऐसे युवाओं को तैयार करना होगा जो सिर्फ तकनीकी रूप से ही नहीं, बल्कि भावनात्मक और संचार कौशल में भी दक्ष हों। ऑटोमोटिव उद्योग की गति को बनाए रखने के लिए कुशल कार्यबल सबसे बड़ा इंजन साबित होगा।

दो वर्ष में 3.5 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 99,446 करोड़ रुपये की रोजगार प्रोत्साहन योजना (ईएलआई) योजना को दी मंजूरी

पहली बार नौकरी करने वालों को दो किस्तों में मिलेगा 15 हजार रुपये, नियोक्ताओं को भी प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये प्रोत्साहन

इस योजना का लाभ 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 के बीच सृजित रोजगार पर लागू होगा।

युवा सहकार टीम

युवाओं को सही दिशा देने और उनकी क्षमताओं का उपयोग भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच रही है कि हर युवा को सीखने, कौशल विकास और कुछ नया करने का अवसर मिले तभी हम 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। उनकी इसी सोच को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट में अगले पांच साल में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पांच प्रमुख योजनाओं के पैकेज की घोषणा की गई थी। बजट में इन योजनाओं पर 2 लाख करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया था। इन्हीं में से एक थी रोजगार प्रोत्साहन योजना (इम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव) जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में मंजूरी दी है।

99,446 करोड़ रुपये की यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से संचालित की जाएगी। इसका

उद्देश्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन करना है। इनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार नौकरी करने वाले होंगे। इस योजना का लाभ 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 के बीच सृजित रोजगार पर लागू होगा। इस योजना के दो भाग हैं जिसमें पहला भाग पहली बार नौकरी के लिए आवेदन करने वालों पर केंद्रित है तथा दूसरा भाग नियोक्ताओं पर केंद्रित है।

पहली नौकरी पर विशेष लाभ

ईएलआई (इम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव) योजना के पहले भाग के तहत निजी कंपनियों में पहली बार नौकरी वाले कर्मचारियों को एक महीने के वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि सरकार की ओर से दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये होगी। यह भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा। पहली किस्त छह महीने की सेवा पूरी करने पर और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को पूरा करने पर दी जाएगी। इस योजना का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनका मासिक वेतन 1 लाख रुपये तक होगा और उनका कर्मचारी भविष्य निधि खाता यानी पीएफ अकाउंट खोला जाएगा। पीएफ अकाउंट से लिंक्ड होने से जहां सरकार को रोजगार के आंकड़े जुटाने में आसानी होगी, वहीं फर्जीवाड़े पर भी सख्ती रहेगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए जमा खाते के बचत साधन में रखा जाएगा, ताकि कर्मचारियों में बचत की आदत विकसित की जा सके। निश्चित अवधि के बाद कर्मचारी इसे निकाल सकेंगे। भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के माध्यम से किया जाएगा। यह राशि उन्हीं युवाओं को मिलेगी जिनका वेतन एक लाख रुपये मासिक से कम होगा

नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहन

इस योजना का दूसरा भाग नियोक्ताओं के लिए है। यदि कोई नियोक्ता 1 लाख रुपये तक वेतन वाले अतिरिक्त कर्मचारियों को न्यूनतम छह महीने तक नौकरी पर रखता है, तो उसे प्रति कर्मचारी ईपीएफ योगदान के लिए प्रति माह 3,000 रुपये तक प्रोत्साहन मिलेगा। इसके तहत 10 हजार रुपये वेतन वाले कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रति कर्मचारी 1,000 रुपये, 10-20 हजार रुपये के वेतन पर 2,000 रुपये और 20 हजार से 1 लाख रुपये तक वेतन वाले कर्मचारियों के लिए 3,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। निजी कंपनियों को दी जाने वाली यह सहायता दो वर्षों तक दी जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जा सकता है। भुगतान सीधे नियोक्ता के पैन से जुड़े बैंक खाते में किया जाएगा। ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड कंपनियों को कम से कम छह महीने के लिए निरंतर आधार पर कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी (50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) या पांच अतिरिक्त कर्मचारी (50 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) नियुक्त करने की आवश्यकता होगी। इससे लगभग 2.60 करोड़ लोगों के अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन राशि मिलने की उम्मीद है।

ईएलआई योजना न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, बल्कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से उन्हें जोड़कर एक सुरक्षित भविष्य भी सुनिश्चित करेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विशेष बल देने से औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि यह योजना भारत को रोजगार और उत्पादन दोनों के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी और 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक सिद्ध होगी। सरकार का इरादा सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के अलावा पहली बार कार्यबल में शामिल होने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करना है।■

रोजगार और कौशल विकास की पांच केंद्रीय योजनाएं

4.1 करोड़ युवाओं के लिए पांच साल में रोजगार, कौशल विकास प्रशिक्षण और अन्य अवसरों के लिए केंद्र सरकार की पांच योजनाएं निम्नलिखित हैं-

- **पहली नौकरी: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता जो दो किस्तों में दी जाएगी।**
- **मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार सृजन: कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराना जो नौकरी के पहले चार साल में दोनों के ईपीएफओ योगदान पर निर्भर होगा।**
- **नियोक्ताओं को प्रोत्साहन: सरकार नियोक्ता को उसके ईपीएफओ योगदान के लिए दो साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3,000 हजार रुपये प्रत्येक महीना भुगतान करेगी।**
- **कौशल विकास प्रशिक्षण: केंद्र प्रायोजित इस योजना के तहत अगले पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं का कौशल बढ़ाया जाएगा और 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का उन्नयन किया जाएगा।**
- **युवाओं के लिए इंटर्नशिप: पांच साल में एक करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप करवाना।**

अलग मंत्रालय से सहकारिता ने भरी नई उड़ान

केंद्र ने राज्यों के समन्वय से सहकारिता में किया व्यापक सुधार

पैक्स से अपेक्स तक हुए सशक्त, सहकारी समितियों की वित्तीय चुनौतियां हुई दूर

टैक्स प्रणाली को तर्कसंगत बनाने से सहकारी संस्थाओं को मिला नया अवसर

युवा सहकार टीम

आधुनिक सहकारिता आंदोलन के लिए 6 जुलाई, 2021 की तारीख अहम मानी जा सकती है। 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को पूरा करने के लिए इसी तारीख को केंद्र सरकार ने अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया था। सहकारिता क्षेत्र के लिए ये चार साल बेमिसाल साबित हुए हैं, जिसे सहकारिता क्षेत्र की दूसरी क्रांति के रूप में भी देखा जा रहा है। अलग मंत्रालय बनने से देश में मंथर गति से चल रही सहकारिता को तेज रफ्तार मिली है। इन चार वर्षों के भीतर सहकारिता क्षेत्र में कुछ अहम पहल की गई है, जिससे सहकारिता की तस्वीर बदलने में मदद मिली है। इस दौरान कानूनी, प्रशासनिक और वित्तीय सुधार पर पूरा जोर दिया गया है, जिससे सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता को प्रोत्साहन मिला है। दो लाख नए पैक्स के गठन का लक्ष्य निर्धारित

कर सभी ग्राम पंचायतों को सहकारिता से जोड़ने का फैसला अहम साबित हुआ है।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री के रूप में अमित शाह ने सहकारिता की निचली इकाई पैक्स से लेकर शीर्ष सहकारी संस्थाओं (अपेक्स) तक में सुधार का व्यापक फैसला लिया जिसे इन चार वर्षों के दौरान लागू किया गया। उन्होंने सहकारिता में सुधार के लिए संघीय ढांचे के अनुरुप राज्यों के सहयोग से इसे मूर्त देना शुरू किया। इसकी शुरूआत कानूनी सुधार से की गई जिसके लिए केंद्र द्वारा तैयार मॉडल कानून को केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सभी राज्यों ने स्वीकार कर अपने यहां सहर्ष लागू किया है। कानूनी सुधार से ठप पड़े पैक्स में कामकाज शुरू हो गया और उनके गठन की खामियों को दूर करने में मदद मिली है। पैक्स में महिलाओं, युवाओं और दलित वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। इसके साथ ही राज्यों में सहकारी संस्थाओं में प्रशासनिक सुधार के साथ चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है।

पैक्स से अपेक्स तक हुए ऑनलाइन

पैक्स से लेकर अपेक्स तक की सहकारी संस्थाओं की पुरानी कार्य प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और कारगर बनाने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने निचली इकाई से लेकर शीर्ष सहकारी संस्था तक को ऑनलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत सभी पैक्स और सहकारी संस्थाओं का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। इससे सहकारी क्षेत्र में धांधली की आशंका सीमित हो गई है। पैक्स कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र सरकार की ओर से एकमुश्त वित्तीय मदद दी जा रही है। एक लाख से अधिक पैक्स में से पहले चरण में 67 हजार पैक्स को कंप्यूटरीकरण के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें से 52 हजार से अधिक पैक्स कंप्यूटरीकृत और ऑनबोर्ड हो चुके हैं, जिससे वे सीधे केंद्रीय सर्वर से

जुड़ गए हैं। इससे जहां कार्य प्रणाली में सुधार हुआ है वहीं कामकाज में पारदर्शिता आई है।

बदली पैक्स की तकदीर

मॉडल कानून लागू करने वाले राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों (पैक्स) को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की योजना शुरू की गई। केंद्रीय सहकारिता मंत्री की पहल पर एक दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों के साथ समन्वय कर दो दर्जन से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों से पैक्स को संबद्ध किया गया। इसी के चलते देश के सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स का कारोबारी दायरा बढ़ने से स्थानीय युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। पेट्रोल पंप, गैस वितरण केंद्र, किसान समृद्धि केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, गोदाम बनाने और रोजगार सृजन के अन्य कई योजनाओं का लाभ पैक्स को मिलने लगा है। यह सब इन्हीं चार वर्षों के भीतर संभव हो सका है।

सहकारी संस्थाओं की पुरानी कार्य प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और कारगर बनाने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने निचली इकाई से लेकर शीर्ष सहकारी संस्था तक को ऑनलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत सभी पैक्स और सहकारी संस्थाओं का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। इससे सहकारी क्षेत्र में धांधली की आशंका सीमित हो गई है।

डेयरी और मत्स्य कोऑपरेटिव को प्रोत्साहन

ग्रामीण भारत के कृषि क्षेत्र में सहकारिता की भूमिका बहुत अधिक है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार देश के ज्यादातर गांव सहकारिता से संबद्ध हैं, लेकिन डेयरी और मत्स्य क्षेत्रों में सहकारिता का प्रसार तुलनात्मक रूप से कम है। सहकारिता ने कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए मत्स्य व डेयरी क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। कृषि क्षेत्र पहले से ही बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारत की तटीय सीमा 7500 किमी है जिसमें मत्स्य पालन और मत्स्य कारोबार की अपार संभावनाएं है। इसी तरह देश में नदियां, झील और गांव-गांव में पोखर एवं तालाबों की संख्या बहुत अधिक है। इसके मद्देनजर आंतरिक मत्स्य पालन की भी संभावनाएं बहुत है। इस क्षेत्र में संलग्न मानव संसाधन गरीब और वंचित तबके के लोग हैं, जिनके लिए सहकारिता एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। इन्हीं सबको देखते हुए सहकारिता मंत्रालय ने मत्स्य सहकारी समितियों के गठन पर ज्यादा जोर दिया है, ताकि उन्हें रियायती दर पर वित्तीय व तकनीकी मदद मुहैया कराई जा सके। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने मत्स्य क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए एनसीडीसी के माध्यम से मदद पहुंचाने की पहल की है। डेयरी सहकारी क्षेत्र की कई संस्थाओं का प्रदर्शन उल्लेखनीय है जिससे लाखों पशुपालकों के जीवन में बदलाव आया है। अमूल जैसी डेयरी सहकारी संस्था वैश्विक स्तर पर अपने झंडे गाड़ रही है।

ग्रामीण भारत के कृषि क्षेत्र में सहकारिता की भूमिका बहुत अधिक है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार देश के ज्यादातर गांव सहकारिता से संबद्ध हैं, लेकिन डेयरी और मत्स्य क्षेत्रों में सहकारिता का प्रसार तुलनात्मक रूप से कम है। सहकारिता ने कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए मत्स्य व डेयरी क्षेत्र को प्राथमिकता दी है।

सहकारी चीनी उद्योग को मिला बूस्टर डोज

बीते चार वर्षों में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की उपलब्धियों में शुगर इंडस्ट्री को प्रमुख रूप से शामिल किया जा सकता है। वित्तीय घाटे, अतार्किक टैक्स प्रणाली और कानूनी चुनौतियों से जूझ रही सहकारी चीनी मिलों के लिए नया मंत्रालय और पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह वरदान साबित हुए हैं। सहकारी क्षेत्र की समस्याओं को चिन्हित कर उन्हें दूर करने का प्रयास पहले चरण में ही कर दिया गया। इनकम टैक्स और जीएसटी जैसी दिक्कतें उन्हें मुश्किलों से उबरने नहीं दे रही थी। नये मंत्रालय के गठन के बाद आये केंद्रीय आम बजट में कई ऐसे प्रावधान लाए गए, जिससे उनकी कठिनाइयां दूर हो गई। सबसे बड़ी बात यह रही कि सहकारी चीनी मिलों के ऊपर 10 हजार करोड़ रुपये का पुराना बकाया भी माफ कर दिया गया। उनके वित्तीय लेनदेन की प्रणाली को आसान बना दिया गया। नगदी भुगतान की सीमा बढ़ा दी गई। चीनी उद्योग से जुड़े एथनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया, जिससे सहकारी मिलों को घाटे से उबरने में मदद मिली है। पुरानी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया गया।

कोऑपरेटिव को कॉरपोरेट की तर्ज पर छूट

सहकारिता क्षेत्र की संस्थाओं पर अतार्किक रूप से लगाए जा रहे इनकम टैक्स से कारोबारी गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित रहती थी, जिसमें जरूरत के मुताबिक आमूल संशोधन कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी

क्षेत्र और कंपनियों के बीच समानता लाने के उद्देश्य से एक करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक की आय वाली सहकारी समितियों के लिए आयकर पर अधिभार को कंपनियों के समान सात प्रतिशत कर दिया गया है जो पहले 12 प्रतिशत था। सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) की दर 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है। पैक्स और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) द्वारा नकद जमा और नकद ऋण की सीमा 20,000 रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये प्रति सदस्य कर दी गई है। 31 मार्च, 2024 तक मैन्यूफैक्चरिंग शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों पर अधिभार सहित 30 प्रतिशत को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच इस संबंध में समानता होगी।

खाद्य सुरक्षा में सहकारिता की भागीदारी

किसानों की आमदनी बढ़ाने वाली योजनाओं पर सहकारिता मंत्रालय ने विशेष बल दिया है। इसी तरह खाद्य सुरक्षा में सहकारिता की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में पहल करते हुए विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू की है। देश के 11 राज्यों में पीएम अन्न भंडारण योजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि संबंधी ढांचागत निर्माण के तहत 500 पैक्स में इन गोदामों की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना के पूरा होने के बाद देश में अनाज भंडारण की क्षमता में सात करोड़ टन तक की वृद्धि हो जाएगी।

सशक्त हुए सहकारी बैंक

सहकारिता मंत्रालय के प्रयासों से सहकारी बैंकों के व्यवसाय में आ रही कठिनाइयों के समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उनकी पहल से शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) अब अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए नई शाखाएं खोल सकेंगे। सहकारी बैंक भी वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों का एकमुश्त निपटान कर सकेंगे। उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त समय सीमा दी गई है। शहरी सहकारी बैंकों के साथ नियमित संपर्क के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक नोडल अधिकारी नियुक्त की मांग पूरी कर दी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शहरी सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को डोर स्टेप सर्विस उपलब्ध कराने की अनुमति दी है। ग्रामीण और शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा को दोगुना से अधिक कर दिया है। ग्रामीण सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक रियल एस्टेट और आवास क्षेत्र को ऋण दे सकेंगे, जिससे उनके व्यवसाय में विविधता आएगी। सहकारी क्षेत्र के उद्यम सहकारी बैंकों से भी बिना किसी गारंटी के ऋण भी प्राप्त कर सकेंगे।

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन की भारी मांग के मद्देनजर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना का फैसला लिया गया है। सहकारिता में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए यह विश्वविद्यालय अहम भूमिका निभाएगा। गुजरात के आणंद में स्थापित होने वाले सहकारी विश्वविद्यालय से देशभर के सहकारी महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को संबद्ध किया जाएगा।■

किसानों की आमदनी बढ़ाने वाली योजनाओं पर सहकारिता मंत्रालय ने विशेष बल दिया है। इसी तरह खाद्य सुरक्षा में सहकारिता की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में पहल करते हुए विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू की है। देश के 11 राज्यों में पीएम अन्न भंडारण योजना का उद्घाटन किया।

सहकार टैक्सी

सहकारिता से बदलेगी परिवहन क्षेत्र की तस्वीर

सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड नाम से पंजीकृत हुई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी

एनसीडीसी, अमूल, नैफेड, नाबार्ड, इफको, कृभको, एनडीडीबी और एनसीईएल हैं प्रमोटर

दिसंबर तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में शुरू होगी यह सहकारी टैक्सी सेवा

युवा सहकार टीम

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसी साल मार्च में संसद में बताया था कि ओला और उबर की तरह जल्द ही सहकारी टैक्सी सेवा की शुरूआत की जाएगी। मोबाइल ऐप आधारित इस टैक्सी सेवा के शुरू होने से न केवल ग्राहकों को विकल्प मिलेगा, बल्कि टैक्सी चालकों को सशक्त बनाकर सहकारी उद्यमिता को बढ़ावा देने और सहकारिता क्षेत्र का विस्तार करने में भी यह मददगार साबित होगा। उनकी यह घोषणा अब मूर्त रूप लेने जा रही है। इसके लिए सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड नाम से एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। उम्मीद की जा रही है कि सहकारिता के माध्यम से देश की पहली टैक्सी सेवा की शुरूआत इसी वर्ष दिसंबर में हो जाएगी। देश के परिवहन क्षेत्र के लिए यह परिवर्तनकारी कदम है।

देशभर की सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने वाली राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) इस सहकारी समिति की मुख्य प्रमोटर है, जबकि देश की प्रमुख सहकारी संस्थाएं अमूल, नैफेड, नाबार्ड, इफको, कृभको, एनडीडीबी और एनसीईएल अन्य प्रमोटर हैं। सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड को 300 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत किया गया है। प्रत्येक प्रमोटर ने प्रारंभिक

चरण में 10 करोड़ रुपए का योगदान देने की प्रतिबद्धता जताई है। देश की दिग्गज सहकारी संस्थाओं का समर्थन मिलने से सहकार टैक्सी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

अंतरिम बोर्ड गठित

सहकारी टैक्सी सेवा के प्रारंभिक परिचालन की देखरेख के लिए एक अंतरिम बोर्ड का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष एनसीडीसी के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर रोहित गुप्ता हैं। बोर्ड के अन्य प्रमुख सदस्यों में वी. श्रीधर (एनडीडीबी), तरुण हांडा (नैफेड), नवीन कुमार (नाबार्ड), संतोष शुक्ला (इफको) और एलपी गॉडविन (कृभको) शामिल हैं। इस सेवा के लिए मोबाइल ऐप विकसित करने के लिए तकनीकी भागीदारों से बातचीत शुरू हो चुकी है। इसे तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए आईआईटी बेंगलुरु जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग की संभावनाएं तलाशी जा रही है। यह सहयोग उद्योग मानकों के अनुरूप तकनीकी विकास, परिचालन प्रणालियों और डिजिटल एकीकरण को सुनिश्चित करेगा। सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड न केवल उपभोक्ताओं को सस्ती, कुशल और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करेगा, बल्कि यह टैक्सी चालकों के लिए एक टिकाऊ और समावेशी आजीविका मॉडल भी स्थापित करेगा। यह पहल सहकारी समितियों के बीच सहयोग के सिद्धांत को मजबूत करते हुए परिवहन क्षेत्र में एक नए युग की शुरूआत करेगी, जो प्रौद्योगिकी, समावेशिता और सहकारी मूल्यों पर आधारित होगा।

ऐप आधारित निजी क्षेत्र की टैक्सी सर्विस से इतर सहकार टैक्सी को सहकारिता की भावना से चलाया जाएगा। इसमें यात्रियों से उचित किराया लिया जाएगा, सरचार्ज और टिप जैसी वसूली नहीं होगी। शुरूआती चरण में लगभग 400-500 ड्राइवरों को इस सेवा से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। छह महीने की सेवा के बाद प्रत्येक ड्राइवर 100 रुपये के पांच शेयर खरीदकर सहकारी समिति के सदस्य बन सकेंगे।

छोटे शहरों में बनेंगे कॉल सेंटर

सहकार टैक्सी सर्विस के माध्यम से टियर-2 और टियर-3 शहरों में रोजगार के अवसर भी पैदा किए जाएंगे। इस सर्विस के लिए इन शहरों में कॉल सेंटर खोले जाएंगे जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। आमतौर पर टैक्सी सर्विस और अन्य सर्विस के कॉल सेंटर मेट्रो शहरों में ही होते हैं, लेकिन सहकारी टैक्सी के मामले में ऐसा नहीं होगा। ये कॉल सेंटर बैक ऑफिस के रूप में काम करते हैं।

यह पहल केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के दृष्टिकोण का परिणाम है, जिन्होंने एक ऐसी सहकारी टैक्सी सेवा की आवश्यकता पर बल दिया था, जो दोपहिया, रिक्शा, टैक्सी और अन्य चार पहिया वाहनों को एक ही मंच पर एकीकृत करे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि इस मॉडल से प्राप्त लाभ सीधे चालकों तक पहुंचेगा, जिससे उनकी आय और जीवन स्तर में सुधार होगा।■

‘सहकार’ ऐप से होगी बुकिंग

यह सहकारी समिति दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में शुरूआती परिचालन करेगी। बाद में इसका विस्तार देश के बाकी हिस्सों में किया जाएगा। सहकारी टैक्सी सेवा के ऐप आधारित प्लेटफॉर्म का नाम ‘सहकार’ होगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहक टैक्सी के अलावा दोपहिया, ई-रिक्शा और अन्य चार पहिया वाहन भी बुक कर सकेंगे। सहकार टैक्सी की सबसे बड़ी विशेषता इसका सहकारी ढांचा है, जिसमें टैक्सी चालक न केवल सेवा प्रदाता होंगे, बल्कि सहकारी समिति के सह-मालिक भी होंगे। यह मॉडल चालकों को निष्पक्ष लाभ वितरण, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी और बेहतर कार्यस्थितियों का अवसर प्रदान करेगा। सहकार टैक्सी को केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं चलाया जाएगा, बल्कि यात्रियों से उचित किराया लिया जाएगा और लाभ का बड़ा हिस्सा ड्राइवरों में समान रूप से बांटा जाएगा। ड्राइवरों की सामाजिक सुरक्षा का भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। इसका स्वामित्व और प्रबंधन पूर्ण रूप से इसके सदस्यों, यानी टैक्सी चालकों के हाथों में होगा। यह सहकारी मॉडल पारदर्शी और लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देगा। इस पहल का मूल मंत्र ‘सहकार से समृद्धि’ है, जो सहकारी मूल्यों पर आधारित समावेशी और टिकाऊ परिवहन सेवाओं को सुनिश्चित करता है।

300

करोड़ रुपए की शेयर पूंजी के साथ पंजीकृत हुई सहकारी समिति

10

करोड़ रुपए का प्रारंभिक योगदान सभी प्रमोटर ने दिया

इंश्योरेंस में भी कोऑपरेटिव, बनेगी नई कंपनी

बीमा क्षेत्र में कोऑपरेटिव का हिस्सा बढ़ा कर जल्द ही पूर्ण स्वामित्व वाली इंश्योरेंस कंपनी बनाई जाएगी

नैफेड के नए उत्पाद, एफपीओ को अनुदान और गोदाम बनाने के लिए पैक्स के साथ अनुबंध को दिया गया औपचारिक रूप

युवा सहकार टीम

सहकारिता क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने और इसका व्यापक विस्तार करने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में अब पूर्ण स्वामित्व वाली सहकारी बीमा कंपनी की शुरूआत की जाएगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में मुंबई में नैफेड द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में इसकी घोषणा की। इस साल अब तक सहकारी क्षेत्र के लिए यह चौथी बड़ी पहल है। इससे पहले देश की पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाने, कोऑपरेटिव टैक्सी सेवा की शुरूआत करने और डेयरी क्षेत्र में तीन नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाने की पहल सहकारिता मंत्रालय द्वारा की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने में ये पहलें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

नैफेड की राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, 'सरकार ने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना का निर्णय लिया है और जल्द ही इसका भूमिपूजन हो जाएगा। कोऑपरेटिव मॉडल पर टैक्सी सेवा की भी शुरूआत होगी, जिसमें टैक्सी ड्राइवर सिर्फ इससे जुड़ा नहीं होगा, बल्कि वह इसमें मालिक की भूमिका में होगा और मुनाफा सीधा उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। साथ ही, बीमा क्षेत्र में कोऑपरेटिव का हिस्सा बढ़ा कर जल्द ही पूर्ण स्वामित्व वाली इंश्योरेंस कंपनी की शुरूआत होगी। इससे कई नए आयाम खुलेंगे।' अभी देश की सहकारी संस्थाओं में से सिर्फ इफको ही बीमा क्षेत्र में मौजूद है, लेकिन संयुक्त उद्यम के जरिये। इस उद्यम का पूर्ण स्वामित्व उसके पास नहीं है। अमित शाह की घोषणा के अनुसार अब जो बीमा कंपनी बनेगी उसका पूर्ण स्वामित्व सहकारी संस्थाओं के पास ही

होगा। इसका खाका कैसा होगा, इसमें कौन-कौन सी सहकारी संस्थाएं होंगी, नई सहकारी कंपनी सामान्य बीमा क्षेत्र (जीआईसी) की होगी या जीवन बीमा क्षेत्र (एलआईसी) की अथवा वह दोनों क्षेत्रों में काम करेगी, इस बारे में अभी फैसला किया जाना बाकी है। नई सहकारी बीमा कंपनी बनने से सहकारिता आंदोलन का और विस्तार होगा और इसे नई मजबूती मिलेगी।

बीमा क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र का प्रवेश देश के नौजवानों के लिए भी नया अवसर उपलब्ध कराएगा। बीमा कंपनियों को बड़ी संख्या में एजेंटों की जरूरत होती है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में। ऐसे में युवाओं के लिए रोजगार का नया रास्ता खुलेगा। अभी बीमा क्षेत्र करीब 23 लाख लोगों को रोजगार देता है। सहकारी क्षेत्र की कंपनी आने से अवसर और बढ़ेंगे।

इस कार्यक्रम में नैफेड के नए उत्पाद, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को अनुदान और गोदाम बनाने के लिए नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के साथ अनुबंध को औपचारिक रूप दिया गया, जो नैफेड की किसान लक्षित गतिविधि का परिचायक है। शाह ने कहा कि नैफेड ने सफलता की ढेर सारी गाथाएं रची हैं। किसान खेत में अपना पसीना बहा कर अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर भारत सरकार को देते हैं और वही अनाज गरीबों को हर महीने 5 किलो निःशुल्क राशन के तौर पर दिया जा रहा है। इस पूरी योजना की रीढ़ एनसीसीएफ और नैफेड हैं। नैफेड के ऐप पर किसान अगर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, तो उनकी सौ प्रतिशत दाल और मक्का नैफेड एमएसपी पर खरीद लेगा। मॉडल ऐप की सफलता को देखते हुए नैफेड आने वाले दिनों में किसानों से सीधी खरीद की शुरूआत करने वाला है। इस व्यवस्था से किसान अपनी फसलों की प्लानिंग अच्छी तरह कर सकता है।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर तीन सहकारी संस्थाओं राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल), राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) की स्थापना से किसानों की उपज को वैश्विक बाजार में बेचने में मदद मिलेगी जिससे इनका मुनाफा किसानों के खाते में जाएगा। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को भारत ब्रांड के साथ भारत ऑर्गेनिक के नाम से विश्व और देश के बाजार में बेचने से परंपरागत और जैविक खेती करने वाले किसानों को फायदा तो होगा ही, साथ ही उपभोक्ताओं को विश्वसनीय तरीके से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी मिल पाएगा। शाह ने कहा कि बीजों के संरक्षण और संवर्द्धन के साथ हम इनकी उत्पादकता बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि दस साल बाद ये तीनों नए राष्ट्रीय कोऑपरेटिव अमूल, नैफेड, इफको, कृभको की तर्ज पर किसानों के लिए बहुत बड़ी कोऑपरेटिव संस्था बनेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने बताया कि लगभग सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया जा चुका है। इनमें से लगभग 52,000 पैक्स लाइव हो चुके हैं। पैक्स को 24 अलग-अलग प्रकार के काम करने की अनुमति देकर उन्हें व्यावहारिक बनाया गया है। केवल कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से ही पैक्स अब 300 विभिन्न योजनाओं के केंद्र बन चुके हैं।

सहकारी क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। लगभग 1.38 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता एनसीडीसी के माध्यम से दी गई है। मछली पालन में 44 गहरे समुद्री ट्रॉलर कोऑपरेटिव के माध्यम से दिया जा रहा है। साथ ही, श्वेत क्रांति 2.0 के माध्यम से डेयरी सेक्टर को भी मजबूत किया जा रहा है। डेयरी क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी को भी बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा देश सिर्फ जीडीपी के आधार पर सशक्त नहीं हो सकता। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में जीडीपी तो बढनी ही चाहिए, परन्तु सभी को रोजगार भी मिलना चाहिए। गांव के गरीबों, युवाओं और महिलाओं को रोजगार युक्त करना है, तो केवल सहकारिता ही एक ऐसा साधन है जो बहुत कम पूंजी में ढेर सारे लोगों को व्यवसाय के साथ जोड़ता है और कम पूंजी में ज्यादा मुनाफे के मंत्र को साकार करता है।■

अभी देश की सहकारी संस्थाओं में से सिर्फ इफको ही बीमा क्षेत्र में मौजूद है, लेकिन संयुक्त उद्यम के जरिये। इस उद्यम का पूर्ण स्वामित्व उसके पास नहीं है। अमित शाह की घोषणा के अनुसार अब जो बीमा कंपनी बनेगी उसका पूर्ण स्वामित्व सहकारी संस्थाओं के पास ही होगा।

खेलो भारत नीति 2025 को कैबिनेट की मंजूरी

बदलेगी खेलों की तकदीर व तस्वीर

भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की नई पहल

वर्ष 2047 तक खेलों में भारत को दुनिया के शीर्ष पांच देशों में पहुंचाने का लक्ष्य

खेलों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने, खेल शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने का प्रावधान

सत्येन्द्र पाल सिंह

भारत को वर्ष 2047 तक खेलों में दुनिया के शीर्ष पांच देशों में पहुंचाने के लक्ष्य के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'खेलो भारत नीति 2025' को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे भारत को खेलों में दुनिया के शीर्ष पांच देशों में शामिल करने की रणनीतिक पहल बताया। पहले इसे राष्ट्रीय खेल नीति (एनएसपी) कहा जाता था जिसे 1984 में पहली बार पेश किया गया था। 'खेलो भारत नीति 2025' अब 2001 की राष्ट्रीय खेल नीति की जगह लेगी। इस नीति में प्रधानमंत्री के भारत को 2047 तक ऐसा राष्ट्र बनाने, जो न केवल विकसित हो, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ तथा अग्रणी हो, के सपने की झलक साफ दिखाई देती है। नई नीति भारत की खेलों में तकदीर व तस्वीर बदल देगी। यह भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने तथा 2036 के ओलंपिक खेलों सहित अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक दूरदर्शी और रणनीतिक रोडमैप प्रस्तुत करती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, 'खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और खेलों का केंद्र बनने के भारत के प्रयासों के लिए 1 जुलाई, 2025 का दिन ऐतिहासिक है।' खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, 'खेलो भारत नीति 2025 जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे एवं खिलाड़ियों के विकास का समर्थन करने अैर भारत को वैश्विक खेलों में एक मजबूत ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक रुपरेखा तैयार करेगी।' केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया, 'खेलो भारत नीति 2025 को बीते दस बरस के अनुभव और विश्लेषण के आधार पर तैयार किया गया है। इसका मकसद भारत को 2047 तक दुनिया के शीर्ष पांच देशों में शामिल कराना है। नई नीति खेलों से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं के लिए एक मजबूत ढांचा मुहैया कराएगी। इसके तहत खेलों को पर्यटन और आर्थिक विकास से जोड़ा जाएगा। खेलों को स्कूली पाठ्यक्रम में बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा। विश्व स्तरीय खेल ढांचा तैयार करने के साथ जमीनी स्तर से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें बेहतरीन कोचिंग दी जाएगी।'

नई खेल नीति को भारत की एथलेटिक संस्कृति को मजबूत करने और राष्ट्र को एक प्रमुख वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की अहम कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। इसका मकसद एक मजबूत एथलीट केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और खेलों को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना है। यह नीति रणनीति, गुणवत्ता, समावेशन, बुनियादी ढांचे की पहुंच और राष्ट्रव्यापी सामुदायिक भागीदारी को प्राथमिकता देती है। इसकी मदद से भारत एक विश्व स्तरीय खेल राष्ट्र बन सकता है जिससे अधिक स्वस्थ, अधिक सक्रिय और अधिक मजबूत नागरिक तैयार होंगे। खेलो भारत नीति 2025 विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ), एथलीटों, डोमेन विशेषज्ञों और सार्वजनिक हितधारकों से जुड़े व्यापक परामर्श का नतीजा है।

खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते रहे हैं पीएम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है, चाहे वह आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली टीम हो या फिर ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ी हों। बीते बरस रोहित शर्मा की अगुआई में जब भारत ने टी20 विश्व कप का खिताब जीता था, तो पूरी टीम को अपने आवास पर बुलाकर उनका दिल खोल कर स्वागत किया था और बधाई दी थी। जबकि आईसीसी वनडे विश्व कप के फाइनल में हारने पर पूरी टीम को बुलाकर उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा था कि आप बहुत बढ़िया खेले, हार जीत खेल का हिस्सा है। इसी तरह, हरमनप्रीत सिंह की अगुआई में 2024 के पेरिस ओलंपिक में लगातार दूसरी बार कांसा जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम की सराहना करने के साथ अगले ओलंपिक में और बेहतर प्रदर्शन की कामना कर खिलाड़ियों से बराबर सीधा संवाद किया।■

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

खेलो भारत नीति 2025 के पांच प्रमुख स्तंभ

1.वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता: इसका मसकसद बुनियादी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक खेल कार्यक्रमों को मजबूत बनाना, प्रतिभाओं की जल्द पहचान और पोषण के लिए तंत्र बनाना है। साथ ही, प्रतिस्पर्धी लीगों और प्रतियोगिताओं की स्थापना को बढ़ावा देना, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में खेल संरचना का विकास करना, प्रशिक्षण, कोचिंग और समग्र एथलीट समर्थन के लिए विश्व स्तरीय प्रणालियां बनाना, राष्ट्रीय खेल संघों की क्षमता और प्रशासन को बढ़ाना शामिल है। एथलीटों के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए खेल विज्ञान, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी अपनाने को प्रोत्साहित करना, प्रशिक्षकों, तकनीकी अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों सहित खेल कर्मियों को प्रशिक्षित और विकसित भी इस नीति के माध्यम से किया जाएगा।

2.आर्थिक विकास के लिए खेल: खेलो भारत नीति 2025 खेलों की आर्थिक क्षमता को मान्यता देती है। इसका मकसद खेल पर्यटन को बढ़ावा देना तथा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोजनों को भारत की ओर आकर्षित करना है। खेल विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के साथ इसमें स्टार्टअप और उद्यमशीलता को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी), कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और नवीन वित्त पोषण पहलों के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की भी इसमें रणनीति बनाई गई है।

3. सामाजिक विकास के लिए खेल: नई खेल नीति सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने में खेलों की भूमिका पर जोर देती है। इसका मकसद केंद्रित कार्यक्रमों के जरिये महिलाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जनजातीय समुदायों और विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी को बढ़ाना, स्वदेशी एवं पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करना एवं बढ़ावा देना है। शिक्षा में खेलों को एकीकृत करके स्वयंसेवा को प्रोत्साहित करना, दोहरे करियर की राह आसान बनाकर खेलों को एक व्यवहार्य करियर विकल्प के रूप में स्थापित करना, खेलों के माध्यम से भारतीय प्रवासियों को शामिल करना भी इसका उद्देश्य है।

4. खेल एक जन आंदोलन: खेलों को राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिए नई नीति का मकसद है राष्ट्रव्यापी अभियानों और समुदाय-आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से जन भागीदारी और फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा देना। स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों आदि के लिए फिटनेस सूचकांक शुरू करना और खेल सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच बढ़ाने की भी इसमें पहल की गई है।

5. शिक्षा के साथ एकीकरण: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप खेलों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने, खेल शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने का नई नीति में प्रावधान किया गया है।

एनवाईसीएस के कौशल विकास से मिली सफलता

युवा सहकार टीम

दिल्ली निवासी 18 वर्षीय जितेश मरोठा एक समय अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित रहते थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि क्या करें जिससे आर्थिक रूप से सक्षम बन सकें और घर परिवार चलाने में मां का हाथ बंटा सकें। पिता के कम उम्र में ही गुजर जाने के बाद उनकी मां ही कामकाज करके जितेश और उसके भाई का पालन-पोषण कर रही थीं। आर्थिक परेशानी के कारण परिवार का जीवन काफी मुश्किलों से चल रहा था। इसी दौरान जितेश को नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) की विकासपुरी शाखा द्वारा संचालित होने वाले कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में पता चला। यहां से उन्होंने सीसीटीवी में तीन महीने का प्रशिक्षण लिया और उसके बाद इसी क्षेत्र में काम करने लगे। आज वह न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त हो गए हैं, बल्कि उनका जीवन भी अच्छा चल रहा है।

अपने संघर्ष के दिनों और सफलता के बारे में युवा सहकार से बातचीत में जितेश ने बताया, 'उन दिनों मेरा परिवार आर्थिक रूप से काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा था। मैं खाली बैठा रहता था। मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करूं। मेरे पास कोई हुनर भी नहीं था। एक दिन मैं अपने घर के पास टहल रहा था, तो मुझे एक सर्वेक्षण टीम खड़ी दिखी जो निःशुल्क कोर्स के पर्चे बांट रही थी और उसके बारे में बता रही थी। मैंने उत्सुकतावश एक पर्चा ले लिया और उनसे बात की। उन्होंने बताया कि युवाओं की प्रतिष्ठित कोऑपरेटिव संस्था एनवाईसीएस इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) के सीएसआर (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) कार्यक्रम के सहयोग से कौशल विकास प्रशिक्षण संचालित कर रही है। एनवाईसीएस की विकासपुरी शाखा में चलने वाले इस कार्यक्रम में टेलरिंग, सीसीटीवी इन्स्टॉलेशन और टेक्निशियन जैसे कोर्स करवाए जाते हैं। ये कोर्स केवल 3 महीने के थे, जो मेरी रुचि से मेल खाते थे। वित्तीय बाधा न होने के कारण मैंने इसे अपने कौशल को बढ़ाने और संभावनाओं को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में देखा। मैंने सीसीटीवी इन्स्टॉलेशन एवं टेक्निशियन कोर्स में दाखिला लिया जिसने मेरे जीवन में सफलता की यात्रा की शुरूआत की।'

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रशिक्षित होकर जितेश मरोठा ने लिखी सफलता की कहानी। आज वह न सिर्फ आर्थिक रूप से सक्षम हो गए हैं, बल्कि उनका और उनके परिवार का जीवन भी पहले के मुकाबले बेहतर हो गया है।

जितेश बताते हैं कि कौशल विकास से परिपूर्ण होने के बाद मेरे लिए अवसरों के द्वार खुल गए। मैंने अपने क्षेत्र में नौकरियों के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया। दृढ़ता और कड़ी मेहनत के साथ मुझे ऐसी नौकरी मिली जिसमें न केवल अच्छा वेतन मिला, बल्कि विकास की संभावनाएं भी थीं। मुझे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने उन्हें खुद पर हावी होने नहीं दिया। मैंने कड़ी मेहनत पर ध्यान केंद्रित किया और सीखना एवं आगे बढ़ना जारी रखा। मेरे दृढ़ संकल्प ने फल दिया और मैं अच्छी आय अर्जित करने लगा। आज मेरे पास खुद की गाड़ी भी है और बैंक में बचत भी बढ़ रही है।

जितेश की कहानी इस बात का प्रमाण है कि दृढ़ संकल्प और सही अवसरों के साथ कोई भी व्यक्ति चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकता है और सफलता हासिल कर सकता है। जितेश ने इसके लिए एनवाईसीएस के सीसीटीवी प्रशिक्षक संतोष सर का दिल से धन्यवाद करते हुए कहा कि मेरी जिंदगी बदलने के लिए जीवन भर मैं इस संस्था का आभारी रहूंगा।■

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
NANO TECHNOLOGY
NANO UREA & DAP
IFFCO KISAN DRONE
असरदार जोड़ी
नैनो यूरिया प्लस
सागरिका
नैनो डी ए पी
IFFCO
NANO UREA PLUS
IFFCO
सागरिका
SAGARIKA
100% प्राकृतिक समुद्री उत्पाद
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
NANO DAP
(8:16:0)
CROP NUTRITION REDEFINED
Less Cost, More Profits
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड
इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017, भारत
फोन नंबर- 91-11-26510001, 91-11-42592626, वेबसाइट www.iffco.coop
इफको नैनो उर्वरकों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया स्कैन करें"

NYCS

National Yuva Co-operative Society Limited

Empowering Financial Independence

Our Services

Loans: Small, medium, and large loans at highly competitive interest rates, catering to the diverse financial needs of our members.
Deposits: Attractive interest rates, with special benefits for senior citizens and women.
Simplified Process: Our streamlined application process and flexible terms ensure that financial assistance is always within reach.

Our Reach

- Presence in All States & Union Territories
- 37 Branches Nationwide
- 600+ Districts Served by Our Representatives
- Central Administration Office (CAO) in Pune, Led by Senior Banking & Finance Professionals

Why Choose NYCS Ltd.?

- **Trusted Expertise** – Over 20 years in financial services.
- **Nationwide Presence** – A rapidly growing network.
- **Member-Focused** – Tailored financial solutions.
- **Youth Empowerment** – Supporting young entrepreneurs.

Contact Us

209, 2nd Floor, A2B,
Vardhman Janak Market,
Janakpuri, New Delhi-58
+91 9205595944
011-45096652/40153681
nycs.ltd@gmail.com
www.nycsltd.com

Together, let's build a brighter financial future!